भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1344

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रोजगार की स्थिति

1344. डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भारी कोयला खनन और बिजली संयंत्रों की उपस्थिति के बावजूद युवा बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सीधी और सिंगरौली जिलों में जिला रोजगार कार्यालय तथा राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं को स्थानीय भारी उद्योगों यथा नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), अडानी और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन (हिंडालको) की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित करने के लिए कोई विशेष कौशल विकास योजना अथवा तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। पीएलएफएस की कार्यप्रणाली में जनवरी 2025 से संशोधन किया गया था। पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, 2025 संशोधित श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि के श्रम बाज़ार संबंधी अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य (सिंगरौली जिले सहित) में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2025 में 4.2% थी। इसके अलावा, 15-29 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) मध्य प्रदेश राज्य (सिंगरौली जिले सहित) में 51.6% था, जबकि देश में 2025 में डब्ल्यूपीआर 41.4% था।

इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सितंबर, 2017 से जुलाई, 2025 की अवधि के बीच 8.23 करोड़ से अधिक (जिनमें से 18.60 लाख मध्य प्रदेश

राज्य से हैं) शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं, जो रोजगार में वृद्धि और बाजार के व्यवस्थित होने का संकेत देते हैं। साथ ही, वर्ष 2024-25 के दौरान ईपीएफओ में 1.29 करोड़ से अधिक (जिनमें 2.84 लाख मध्य प्रदेश राज्य से हैं) शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं।

एनसीएस पोर्टल नियोक्ताओं तथा रोजगार चाहने वालों को एक मंच पर इकट्ठा करता है ताकि देश के रोजगार चाहने वालों को रोजगार के अवसर तथा करियर संबंधी सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसके अलावा, एनसीएस पोर्टल पर प्रदत्त रोजगार के अंतिम आकड़े प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, प्रदत्त रोजगार के आंकडें नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से सूचित की गई जानकारी पर निर्भर करते हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में (जिसमें मध्य प्रदेश का सिंगरौली ज़िला भी शामिल है) विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) लागू कर रही है (मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले सहित)। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यावित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****